हनीट्रैप में खुलासा : श्वेता जैन ही है मास्टरमाइंड

जेल में बनी दोस्ती से खड़ा किया करोड़ों की उगाही का नेटवर्क

- एक करोड़ की रंगदारी में 5 आरोपी पुलिस रिमांड पर
- नेताओं और कारोबारियों को बनाते थे निशाना

नव भारत न्यूज

इंदौर, 20 मई. हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग कांड की जांच में पुलिस ने एक संगठित गैंग का खुलासा किया है, जो पिछले दो वर्षों से नेताओं, कारोबारियों और रसूखदार लोगों को फंसाकर करोड़ों की उगाही कर रहा था. शराब कारोबारी हितेंद्र सिंह ठाकुर उर्फ चिंटू ठाकुर से एक करोड़ रुपए की मांग के मामले में भोपाल में रहने वाली श्वेता विजय जैन को गिरोह की मास्टरमाइंड बताया है.

पुलिस ने इस मामले में श्वेता जैन, अलका दीक्षित, जयदीप दीक्षित, लाखन चौधरी और जितेंद्र पुरोहित को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था, जहां से सभी को छह दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है.

क्राईम ब्रांच की जांच में सामने आया कि श्वेता जैन और शराब तस्करी से जुड़ी अलका दीक्षित की मुलाकात जिला जेल में हुई थी. यहीं दोनों के बीच हनीट्रैप के जरिए ब्लैकमेलिंग का नेटवर्क खड़ा करने की योजना बनी थी. जेल से बाहर आने के बाद दोनों ने मिलकर प्रभावशाली लोगों को निशाना बनाना शुरू किया. अलका दीक्षित कथित रूप से युवतियों के जरिए लोगों को जाल में फंसाती थी, जबकि श्वेता पूरे नेटवर्क को संचालित करती थी. आपत्तिजनक फोटो व वीडियो बनाकर पीड़ितों से मोटी रकम वसूली जाती थी.

क्राईम ब्रांच सूत्रों के अनुसार गिरोह ने कई हाईप्रोफाइल लोगों को अपना शिकार बनाया, लेकिन बदनामी के डर से अधिकांश पीड़ित सामने नहीं आए. जांच में यह भी सामने आया कि पीथमपुर में रहने वाला लाखन चौधरी खुद को भाजपा पदाधिकारी बताकर प्रॉपर्टी कारोबार की आड़ में संभावित शिकार तलाशता था. वहीं देवास में रहने वाला जितेंद्र पुरोहित , वसूली के तरीकों में सहयोग करता था.

वहीं मामले में इंटेलिजेंस शाखा में पदस्थ प्रधान आरक्षक विनोद शर्मा की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है. पूछताछ में उसने अलका से संपर्क की बात स्वीकार की है. आरोप है कि अलका उसे जीजा जी कहकर बुलाती थी और ब्लैकमेलिंग के तरीकों पर सलाह लेती थी. पुलिस को शक है कि उसने आरोपियों को दबाव बनाने के तरीके बताए.

जांच के दौरान रेशू नाम की एक महिला का भी खुलासा हुआ है, जो आसानी से नेताओं तक पहुंच बनाकर उन्हें फंसाती थी. आरोप है कि उसने दिल्ली के एक नेता से डेढ़ करोड़ रुपए वसूले और उस रकम से लग्जरी कार व संपत्ति खरीदी, पुलिस अब उसकी तलाश में जुटी है.

क्राइम ब्रांच की जांच में यह भी सामने आया है कि गैंग के कुछ तार ड्रग्स और अवैध हथियार नेटवर्क से जुड़े लोगों तक पहुंचते हैं. मामले में पुलिस ने 40 से अधिक अधिकारियों की सात टीमें बनाकर इंदौर और भोपाल में एक साथ छापेमारी की और पांच मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है. कारोबारी चिंटू ठाकुर के मामले में आरोपियों ने पहले प्रॉपर्टी डील के बहाने संपर्क किया और 50 प्रतिशत हिस्सेदारी का दबाव बनाया. मना करने पर युवती के जरिए आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सुपर कॉरिडोर पर कार रोककर एक करोड़ रुपए की मांग की गई और वायरल करने की धमकी दी गई.

गैंग ऐसे करता था वसूली...

पहले प्रॉपर्टी या संपर्क के बहाने टारगेट से नजदीकी बढ़ाते थे, फिर युवती के जरिए आपत्तिजनक स्थिति में फंसाकर फोटो वीडियो तैयार करते थे. इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मोटी रकम की डिमांड की जाती थी. इनकार करने पर सार्वजनिक बदनामी और केस में फंसाने का दबाव बनाया जाता था. जबकि कुछ मामलों में रास्ता रोककर सीधे धमकाकर वसूली भी की जाती थी.

> **संगठित ब्लैकमेलिंग के पुख्ता साक्ष्य**
>
> पूरे मामले में डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि शिकायत के बाद गंभीरता से जांच शुरू की गई. आरोपियों के खिलाफ संगठित ब्लैकमेलिंग और रंगदारी के पुख्ता साक्ष्य मिले हैं. नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी जांच की जा रही है और जल्द और खुलासे हो सकते हैं.

> **आरोपियों के आपसी संबंध और मुलाकात**
>
> श्वेता जैन और अलका दीक्षित की मुलाकात जिला जेल में हुई. जेल में ही हनीट्रैप नेटवर्क की योजना बनाई गई. जमानत के बाद दोनों ने संपर्क बनाए रखा और गैंग तैयार कर ली. इसके बाद लाखन चौधरी, जयदीप दीक्षित और जितेंद्र पुरोहित बाद में जुड़े. सभी मिलकर अलग अलग भूमिकाओं में नेटवर्क संचालित कर रहे थे.

मध्य क्षेत्रीय परिषद् की अगली बैठक उज्जैन में होगी

- अनौपचारिक कैबिनेट में सीएम ने दी जानकारी

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 20 मई. मध्य क्षेत्रीय परिषद् की अगली बैठक वर्ष 2027 में उज्जैन में होगी. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 19 मई को बस्तर में परिषद् की 26वीं बैठक में इस आशय की सहमति दे दी है.

इस बात का खुलासा बुधवार को मंत्रालय में अनौपचारिक कैबिनेट के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया. इस दौरान सीएम ने बताया कि मध्य क्षेत्रीय परिषद् की बैठक लेने के बाद केन्द्रीय गृह मंत्री शाह उज्जैन में सिंहस्थ-2028 की तैयारी को लेकर हो रही व्यापक नागरिक व्यवस्थाओं, मानव प्रबन्धन एवं आपदा प्रबंधन का भी मुआयना करेंगे.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मप्र नक्सल मुक्त हो चुका है. केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने मध्य क्षेत्रीय परिषद् की 26वीं बैठक बस्तर में करके देश में नक्सलवाद की समाप्ति का जन संदेश दिया है. उज्जैन में परिषद की 27वीं बैठक होगी. उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री शाह द्वारा पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना, विशेष पुलिस महानिदेशक पंकज श्रीवास्तव सहित नक्सल उन्मूलन अभियान में सक्रिय योगदान देने वाले पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया है.

मां वाग्देवी की मूल प्रतिमा लंदन से वापस लाएगी सरकार

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने धार जिले की भोजशाला परिसर को लेकर मप्र उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि मप्र शांति का टापू है. प्रदेश में कानून व्यवस्था नियंत्रण हमारी प्राथमिकता है. इसमें कोई ढिलाई नहीं बरती जायेगी. उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने करीब 750 साल पुराने और धार्मिक/ईश वंदना से जुड़े इस मसले का सकारात्मक एवं शांतिपूर्ण समाधान किया है. सरकार इस विषय से जुड़े सभी पक्षों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उच्च न्यायालय के निर्णय का पालन करायेगी. उन्होंने कहा कि मप्र सरकार मां वाग्देवी की वास्तविक प्रतिमा विदेश से स्वदेश लाने के लिए केन्द्र सरकार के साथ हर जरूरी प्रयास एवं समन्वय करेगी. बाद में कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने भी कहा कि लंदन से मां वाग्देवी की प्रतिमा लाने के लिए जरुरी प्रयास किए जाएंगे.

ट्विशा मौत के मामले में सीबीआई जांच का आश्वासन

- मुख्यमंत्री मोहन से मिले ट्विशा शर्मा के पिता

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 20 मई. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में उनके पिता नवनिधि शर्मा ने मुलाकात की. बुधवार को इस मुलाकात के दौरान ट्विशा के मामले में रिटायर्ड सैनिक भी नवनिधि शर्मा के साथ रहे. इस मौके पर मुख्यमंत्री यादव ने ट्वीशा की मौत के मामले में सीबीआई जांच कराने का आश्वासन दिया है.

इसके साथ ही मुख्यमंत्री मोहन ने कहा कि ट्विशा के पार्थिव शरीर के दुबारा पीएम कराने को लेकर कोर्ट से निर्देश मिलने पर प्रदेश सरकार दिल्ली एम्स में पीएम कराने के लिए व्यवस्था करेगी. मुख्यमंत्री यादव से मिलकर ट्विशा के पिता ने सास की जमानत रद्द कराने के आवेदन संबंधी विषय पर चर्चा की. मुख्यमंत्री मोहन ने नवनिधि शर्मा को कार्रवाई को लेकर आश्वासन दिया है.

ट्विशा के शव के दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने की मांग के मामले में सुनाई करते हुए भोपाल कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है. शव को एयर कंडीशनर वाले मॉर्च्युरी में सुरक्षित रखा जाने का निर्देश कोर्ट की तरफ से दिया गया है. परिजनों के शव नहीं लेने पर ऐसी स्थिति में डीकंपोज होने से बचाया जा सकता है. ट्विशा की मौत के 8 दिन बाद भी परिजनों ने शव नहीं लिया है और लगातार मामले में सरकार और प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं.

जानकारी के मुताबिक ट्विशा की मौत के मामले राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है. मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए महिला आयोग ने प्रदेश सरकार से सात दिन में रिपोर्ट मांगी है. जानकारी के अनुसार आयोग ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते ट्विशा की शादी केवल 5 महीने में ही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत को लेकर सवाल किया है. ट्विशा के मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पर दहेज उत्पीड़न, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं. ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा ने राज्यपाल से रिटायर्ड जज और ट्विशा के ससुर गिरिबाला सिंह को कंज्यूमर फोरम के पद से हटाने के लिए पत्र लिखा है. नवनिधि शर्मा ने राज्यपाल को पत्र लिखकर मामले में कार्यवाही की मांग की है.

शादी का झांसा देकर युवती से लगातार बनाए शारीरिक संबंध

इंदौर. किशनगंज थाना क्षेत्र से एक युवक ने शादी का वादा कर 26 वर्षीय युवती की जिंदगी बर्बाद कर दी.लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाने के बाद अब आरोपी शादी के वादे से मुकर गया. घटना किशनगंज थाना क्षेत्र के पिगडंबर इलाके की है. 26 वर्षीय पीड़िता ने थाने पहुँचकर आरोपी रंजीत यादव के खिलाफ गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई है. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी रंजीत ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया था और जल्द ही शादी करने का वादा दिया था. इस भरोसे के बाद आरोपी लगातार पीड़िता की इच्छा और शादी के वादे की आड़ में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा.

सुको का लोकायुक्त से आरटीआई पर सवाल

छूट की वैधता पर सरकार से जवाब तलब

भोपाल, 20 मई. सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश लोकायुक्त संगठन को सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून से दी गई छूट पर कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है. अदालत ने पूछा कि किस कानूनी आधार पर लोकायुक्त को आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया है और क्या यह संगठन खुफिया या सुरक्षा एजेंसी की श्रेणी में आता है.

जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चांदुरकर की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि सरकार ऐसा कोई ठोस रिकॉर्ड पेश नहीं कर सकी, जिससे यह साबित हो कि लोकायुक्त खुफिया एजेंसी की तरह कार्य करता है. कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि

2011 की अधिसूचना, जिसके जरिए यह छूट दी गई थी, प्रथम दृष्टया आरटीआई कानून की भावना के विपरीत प्रतीत होती है.

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरटीआई का उद्देश्य सरकारी संस्थाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है. अदालत ने मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन और महाधिवक्ता प्रशांत सिंह को 20 मई को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं.

> कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, तो 2011 की अधिसूचना को रद्द किया जा सकता है. साथ ही, सरकारी वकीलों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए उनके पैनल की समीक्षा के संकेत भी दिए गए हैं.

संघ प्रमुख भागवत शहडोल पहुंचे

शहडोल. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत आज शहडोल पहुंचे, जहां वे तीन

दिवसीय प्रवास के दौरान संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग में शामिल होंगे. सूत्रों के अनुसार श्री भागवत सुबह कटनी से सड़क मार्ग द्वारा शहडोल स्थित सरस्वती स्कूल पहुंचे. यहां मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित 20 दिवसीय कार्यकर्ता विकास वर्ग में लगभग 650 शिक्षक और शिक्षार्थी शामिल हैं. श्री भागवत शिविर के दौरान विभिन्न बौद्धिक सत्रों को संबोधित करेंगे और संघ की विचारधारा पर मार्गदर्शन देंगे.

मंत्री टेटवाल और पंवार ई-रिक्शा से पहुंचे मंत्रालय

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 20 मई. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देशवासियों से किए गए ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण के आह्वान को आत्मसात करते हुए, बुधवार को कौशल विकास एवं रोजगार राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार गौतम टेटवाल और मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास स्वतंत्र प्रभार नारायण सिंह पंवार कैबिनेट बैठक में शामिल होने के लिए ई-रिक्शा से मंत्रालय पहुंचे.

सुरक्षित पर्यावरण का यही आधार-ईंधन बचत हर बार, का संदेश देते राज्यमंत्री टेटवाल कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसाधनों के संयमित उपयोग का जो आह्वान किया है, उसे आत्मसात कर हम सभी को अपने आचरण से दूसरों को प्रेरित करना चाहिए. टेटवाल और मंत्री पंवार ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि हम सभी को पेट्रोल-डीजल की खपत को कम करने, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और ऊर्जा बचत को एक जनआंदोलन बनाने का संकल्प लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किए गए छोटे-छोटे प्रयास ही भविष्य में एक आत्मनिर्भर, स्वच्छ एवं सशक्त भारत के निर्माण की मजबूत नींव तैयार करेंगे.

28 तक होगी गेहूं खरीदी

भोपाल. प्रदेश में अब समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी 28 मई तक होगी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस संबंध में बुधवार को घोषणा की. गेहूं खरीदी की तिथि अब पांच दिन और बढ़ गई. डॉ. यादव ने कहा कि देश में सर्वाधिक गेहूं खरीदी करने वाला राज्य मप्र है. गेहूं खरीदी का लक्ष्य 75 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन किया गया है, जिसकी खरीदी सरकार के माध्यम से की गई है. इसके साथ ही उन्होंने गेहूं खरीदी की अंतिम तिथि 23 मई से बढ़ाकर 28 मई करने की घोषणा की. अभी तक 12 लाख 56 हजार 952 किसानों से 93 लाख 31 हजार 177 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है. किसानों को 19 हजार 423 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है.

बंडोल-नेमावर योजना पर खर्च होंगे 593 .24 करोड़

इस संबंध में पेश प्रस्ताव को कैबिनेट ने दी हरी झंडी

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 20 मई. सिवनी की बंडोल और देवास की नेमावर समूह जल प्रदाय योजना पर 593 करोड़ 24 लाख रुपये खर्च होंगे. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में इस संबंध में पेश प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई. स्वीकृति अनुसार सिवनी की बंडोल समूह जल प्रदाय योजना की मूल स्वीकृत लागत राशि 232 करोड़ 57 लाख रुपये के स्थान पर पुनरीक्षित योजना लागत राशि 266 करोड़ 17 लाख रुपये की स्वीकृति दी है.

देवास की नेमावर समूह जल प्रदाय योजना की मूल स्वीकृत लागत राशि 237 करोड़ रुपये के स्थान पर 327 करोड़ 07 लाख रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी है. दरअसल बंडोल समूह जल प्रदाय योजना के क्रियान्वयन में 4 ग्रामों एवं 30 बसाहटों को तथा नेमावर समूह जल प्रदाय योजना के क्रियान्वयन में 21 ग्रामों और 11 छूटी हुई बसाहटों को अतिरिक्त रूप से शामिल करने के साथ ही जल जीवन मिशन की गाइडलाइन अनुसार ग्रामीण

परिवारों को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन से जोड़ने के लिए जल वितरण नलिकाओं, क्लीयर वॉटर राइजिंग मैन, उच्च स्तरीय टंकियों एवं नल कनेक्शन के कार्यों में बढोत्तरी होने के कारण यह पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है.

डॉ यादव ने सतीश उपाध्याय को दी बधाई

डॉ मोहन यादव ने मध्यप्रदेश भाजपा के सह-प्रभारी एवं नई दिल्ली के मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक सतीश उपाध्याय को दिल्ली जल बोर्ड में उपाध्यक्ष बनाए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं. डॉ यादव ने कहा कि निश्चित ही उनके अनुभव, संगठनात्मक कौशल एवं जनसेवा के संकल्प से जन कल्याणकारी प्रयासों में नया अध्याय लिखा जाएगा.

आठ जिलों में हेल्प डेस्क होंगे स्थापित

इसी क्रम में महिला एवं बाल विकास के तहत महिला एवं बाल सुरक्षा से संबंधित योजनाओं के वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निरंतर संचालन के लिए कुल 156 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है. स्वीकृति अनुसार चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए 113 करोड़ 50 लाख रूपये, केयर एण्ड सपोर्ट टू विक्टिम अंडर पॉक्सो योजना के लिए 27 करोड़ 50 लाख रुपये और शौर्य दल योजना के लिए 15 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है. स्वीकृति अनुसार चाइल्ड हेल्पलाइन अन्तर्गत पूर्व से स्थापित 51 जिलों के साथ-साथ नवगठित 4 जिलों निवाड़ी, मैहर, पांढुर्णा एवं मऊगंज में जिला स्तरीय इकाईतथा 9 पूर्व से स्थापित हेल्प डेस्क के साथ-साथ 04 रेल्वे स्टेशन कटनी, बीना सागर, मेघनगर झाबुआ, सिंगरौली में रेल्वे स्टेशन हेल्प डेस्क और 08 बस स्टैंड छतरपुर, बुरहानपुर, सिवनी, ग्वालियर, झाबुआ, नीमच, सतना एवं बालाघाट में हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी. इसी तरह लोक सेवा गारंटी अधिनियम को भी अगले पांच वर्ष तक क्रियान्वयन के लिए 360 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है. वहीं श्रमिक कल्याण की विभिन्न योजनाओं को अगले पांच वर्ष तक बनाए रखने के लिए 1779.07 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के लिए 373 करोड़ 38 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जारी रहेगी

कैबिनेट ने किसानों को फसल हानि या क्षति होने पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आगामी 05 वर्षों तक निरंतर क्रियान्वयन के लिए 11 हजार 608.47 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी है. वहीं वृद्धजनों, कल्याणी महिलाओं और दिव्यांगजन की पेंशन योजना को भी अगले पांव वर्ष तक बनाए रखने के लिए 15,184.42 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है.

बिचौलियों पर लगी लगाम | महाकाल में 250, मंगलनाथ पर 100 और कालभैरव के 500 में शीघ्र दर्शन

अब रसीद कटाइए और सीधे दर्शन पाइए

- मदिरा का लगता है भगवान् को भोग

उज्जैन, 20 मई. उज्जैन धर्मनगरी श्री महाकालेश्वर मंदिर में वर्षों से श्रद्धालुओं के लिए शीघ्र दर्शन की सशुल्क व्यवस्था संचालित है. अब इसी व्यवस्था का विस्तार मंगलनाथ मंदिर और श्री काल भैरव मंदिर तक कर दिया गया है. बुधवार को काल भैरव मंदिर पर 500 में वीआईपी दर्शन की व्यवस्था लागू कर द गई.

भगवान महाकाल के सेनापति के तौर पर प्रसिद्ध बाबा काल भैरव को मदिरा का भोग लगाया जाता है, देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु महाकाल दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, उतनी ही तादात में यात्री यहां भी आते हैं, चुनाव में जीत राजनीति में उच्च पद और व्यापार व्यवसाय में उन्नति के लिए यहां पर मनोकामना मांगी जाती है, ऐसे में यहां पर भगवान काल भैरव को मदिरा का भोग भी लगाया जाता है,कई वीआईपी फ्लाइट से इंदौर आने के बाद ताबड़तोड़ उज्जैन आते हैं और उन्हें शीघ्र वापस जाना होता है ,ऐसे में 500 का शुल्क यहां लागू कर दिया गया है जिसका अच्छा खासा प्रतिसाद पहले ही दिन मिला.

बिचौलियों ने दिया आइडिया: हाल ही में उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने कालभैरव मंदिर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का अवलोकन किया था और मंदिर के कायाकल्प की दिशा में कई सुधारों की बात कही. लगातार ऐसी शिकायतें सामने आ रही थीं कि कुछ बिचौलिए शीघ्र दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं से राशि लेकर उन्हें ठगी का शिकार बना रहे थे. कई बार मोबाइल फोन बंद कर फरार होने जैसी घटनाओं ने भक्तों को परेशान किया.इन्हीं शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने अधिकृत टिकट प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया. अब श्रद्धालु मंदिर परिसर के अधिकृत काउंटर से रसीद प्राप्त कर निश्चिंत होकर दर्शन कर सकते हैं. सामान्य दर्शन व्यवस्था पूर्ववत नि:शुल्क जारी रहेगी.

पहले ही दिन मिला उत्साहजनक प्रतिसाद: बुधवार को एसडीएम एल.एन. गर्ग ने मंदिर पहुंचकर नई व्यवस्था का जायजा लिया. पहले ही दिन शीघ्र दर्शन टिकटों से लगभग 1 लाख की आय मंदिर को प्राप्त हुई. मंदिर प्रबंधन के अनुसार यह व्यवस्था देर से शुरू हुई, पर अब इसे सुव्यवस्थित रूप से लागू कर दिया गया है. भविष्य में इसे ऑनलाइन करने की भी तैयारी है.

किस मंदिर पर कितना शुल्क

महाकाल मंदिर में श्रद्धालु 250 की अधिकृत रसीद कटवाकर निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत शीघ्र दर्शन कर सकते हैं. मंगलनाथ मंदिर में यह सुविधा 100 शुल्क पर उपलब्ध है. वहीं विश्वप्रसिद्ध कालभैरव मंदिर में बुधवार से 500 की सशुल्क विशेष दर्शन व्यवस्था लागू कर दी गई है, जिसके माध्यम से श्रद्धालु लंबी कतारों से बचते हुए सीधे गर्भगृह के समीप पहुंचकर बाबा के दर्शन कर सकेंगे और मदिरा का भोग भी अर्पित कर सकेंगे.

इंदौर में विश्वास सारंग बोले- नवाचार से बदलेगा भविष्य

भोपाल, 20 मई. मध्यप्रदेश के सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने इंदौर में आयोजित ब्रिक्स यूथ इन्ट्रेप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग-2026 को संबोधित करते हुए कहा कि ब्रिक्स राष्ट्र आज विकासशील देशों की आकांक्षाओं, नवाचार क्षमता और आर्थिक शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. कार्यक्रम में भारत सरकार की युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे सहित ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि, स्टार्टअप लीडर्स, नीति निर्माता और युवा उद्यमी मौजूद रहे. सारंग ने कहा कि 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भारतीय भावना विश्व को समावेशी विकास और सहयोग का संदेश देती है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत नवाचार, उद्यमिता और युवा सशक्तिकरण के क्षेत्र में वैश्विक भागीदार बनकर उभर रहा है. उन्होंने बताया कि 2006 में शुरू हुआ ब्रिक्स समूह अब 11 देशों तक विस्तारित हो चुका है और वैश्विक जीडीपी में 35 से 40 प्रतिशत योगदान देता है.